

विचार बिन्दु

श्वास की क्रिया के समान हमारे चरित्र में एक ऐसी सहज क्षमता होनी चाहिए। जिसके बल पर जो कुछ प्राप्य है वह अनायास ग्रहण कर लें और जो त्याज्य है वह बिना क्षोभ के त्याग सकें। –टैगोर

बेहतर कल की तरफ बढ़ता हमारा देश

भारत में हर दस बरस में जनगणना होती रही है। जनगणना से जो जानकारीयां प्राप्त होती है उनका उपयोग देश की अद्यावधि प्रगति का आकलन करने के लिए तथा भावी योजनाओं के निर्माण के लिए होता है। हमारे देश में अब तक आखिरी दफा जनगणना सन् 2०11 में हुई थी। इसके बाद वाली जनगणना सन् 2०21 में होनी थी परंतु कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब कोविड तो अतीत हो चुका है परंतु जनगणना की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही है। कुछ अपुष्ट सूत्रों के अनुसार देश की आगामी दशकीय जनगणना सन् 2०2६-27 में हो सकती है। लेकिन इस बीच अन्य अनेक सूत्रों से विभिन्न जानकारीयां प्राप्त होती रहती हैं जो हमें अपने देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार करने के लिए प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध कराती हैं। ऐसी ही कुछ जानकारीयां हमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी संपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (संक्षेप में एसआरएस) की सन् 2०23 की रिपोर्ट से मिली हैं। बता दूं कि सन् 2०23 की यह रिपोर्ट सितम्बर, 2०25 में जारी हुई है इसलिए यही नवीनतम रिपोर्ट है। यहीं यहाँ भी बता दूं कि भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा करवाया जाने वाला यह सर्वेक्षण दुनिया के सबसे विशाल जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों में एक माना जाता है।

इस एसआरएस रिपोर्ट में भारत और इसके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्यतः जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक विकास दर और शिशु मृत्यु दर की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई है। कहना अनावश्यक है कि जनगणना के आंकड़ों के अभाव में ये आंकड़े भी हमें अपने देश की प्रगति और भावी योजनाओं के बारे में विचार करने में सहायक साबित होंगे। इस रिपोर्ट से सबसे अहम जानकारी तो यह मिलती है कि देश ने अपनी जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने में भारी सफलता प्राप्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच दशकों में देश की जन्म दर में भारी कमी आई है। 1971 में जन्म दर 3६.9 थी जो 2023 में घटकर 1८.4 रह गई है। केवल इतना ही नहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर के बीच का फासला भी काफी कम हुआ है। पांच दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर शहरी क्षेत्रों की जन्म दर की तुलना में बहुत ज्यादा थी। अब ऐसा नहीं रह गया है, हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर अभीभी ज्यादा है। सन् 2०23 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर 25.8 बिहार में है जबकि सबसे कम जन्म दर 1०.1 अंडमान निकोबार में है। हम अपने राजस्थान की बात करें तो यहां जन्म दर 22.9 है। शहरी क्षेत्रों में यह 2०.1 है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अधिक, 23.9 है। जन्म दर की गणना के साथ-साथ लिंगानुपात की गणना भी की जाती है। लिंगानुपात का आशय यह होता है कि प्रति एक हजार पुरुष शिशुओं के सामने कितनी बालिका शिशु हैं। सन 202०-22 में जहां यह अनुपात 914 था वहां 2023 में यह बढ़कर 917 हो गया है। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 925 है जबकि टाामीण क्षेत्रों में 914 ही है। सर्वाधिक छत्तीसगढ में 974 है तो सबसे कम उत्तराखण्ड में 8६8 है। इसका आशय यह है कि अब पहले की तुलना में ज्यादा बच्चियां इस दुनिया में आ रही हैं। भारत में गर्भ में लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या की चर्चाओं के संदर्भ में यह वृद्धि उत्साहवर्धक है।

सारी अन्य बातों के देश एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है उसके बढ़ने की गति हमारी अपेक्षाओं से कम हो, यह निश्चित है कि वह बढ़ रहा है। हम यही कामना कर सकते हैं कि आगे बढ़ने की यह गति और अधिक तेज हो और हमारी सरकारें इस मानव संसाधन का अधिक सार्थक उपयोग करे और इस आबादी को बेहतर ज़िंदगी देने के अपने प्रयासों को और अधिक गति दे।

जन्म दर की चर्चा मृत्यु दर की चर्चा के बगैर अधूरी है। असल में तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को मिलाकर ही यह समझा जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। मृत्यु दर की गणना के परिणाम को ऐसे समझा जाना चाहिए कि किसी एक खास इलाके में प्रति एक हजार लोगों में से कितने काल का ग्रास बन रहे हैं, वहीं वहां की मृत्यु दर कहलाती है। यह जानना सुखद है कि पिछले पांच दशकों में हमारे देश में मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। इसका श्रेय बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षाओं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ी हुई जागरूकता और बेहतर जीवन स्थितियों को दिया जा सकता है। 1971 में देश

में मृत्यु दर 14.9 थी जो 2023 में घटकर ६.4 रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह इसी अवधि में 7.2 से घटकर ६.8 और शहरी क्षेत्रों में ६.० से 5.7 हुई है। अपने राजस्थान में वर्तमान मृत्यु दर 5.9 है। शहरों में यह 5.६ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6.० है। 2023 में सर्वाधिक मृत्यु दर ८.3 छत्तीसगढ में तो सबसे कम 4.० चंडीगढ में पाई गई है। और जब हम मृत्यु दर की बात कर रहे हैं तो शिशु मृत्यु दर की चर्चा भी कर लेनी चाहिए। असल में शिशु मृत्यु दर को स्थूल रूप से किसी देश या क्षेत्र विशेष का समग्र स्वास्थ्य परिचायक तथ्य माना जाता है। किसी खास इलाके में होने वाले एक हजार जन्मों में से एक वर्ष तक की आयु वाले कितने बच्चे काल कवलित हो जाते हैं उसी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह देखना बहुत आश्चरित्दायक है कि जहां 1971 में यह शिशु मृत्यु दर 129 थी वहीं 2023 में यह बहुत कम होकर मात्र 25 रह गई है। हालांकि यह संख्या भी अपेक्षणीय नहीं है, यह देखा जाना चाहिए कि हम कहां से कहां आ सके हैं। पिछले एक दशक में ही हमारी शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 25 हुई है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 28 और शहरी क्षेत्रों में 18 है। राजस्थान में यह शिशु मृत्यु दर टाामीण क्षेत्रों में 31, शहरी क्षेत्रों में 23 और समग्रतः 29 है। देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 37 छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है जबकि सबसे कम शिशु मृत्यु दर केवल 3 मणिपुर में है। शिशु मृत्यु दर की एक और गणना अंडर 5 मृत्यु दर के रूप में भी की जाती है। पिछले केवल एक बरस में यह अंडर 5 मृत्यु दर 3.० से घटकर 2.9 हो गई है। यहां यह बात खास तौर पर गौर तलब है कि इस उत्साह बढ़ाने वाली गिरावट के बावजूद यह एक त्रासद तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम हर चालीस में से एक शिशु अपनी उम्र का एक साल पूरा होने से पहले यह दुनिया छोड़ जाता है।

इस सर्वेक्षण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में ये हैं: सन् 2०23 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र प्रजनन दर 1.9 है। समग्र प्रजनन दर का आशय यह है कि कोई स्त्री अपनी प्रजनन क्षमता वाले वर्षों में औसतन कुल कितने बच्चों को जन्म देगी। दूसरी बड़ी बात यह कि देश में 14 बरस तक की आयु वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, और इसी के बरक्स यह तथ्य भी कि कामकाजी उम्र (15 से 59) वालों की संख्या बढ़ रही है। जहां तक कामकाजी उम्र वालों की संख्या बढ़ने की बात है, 1971-81 वाले दशक में यह 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 5६.3 प्रतिशत हुई थी। इसके बाद 1991 से 2023 के बीच यह बढ़कर 66.1 प्रतिशत हो गई है। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी उम्र के लोग 68.8 प्रतिशत हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे थोड़े कम, 64.6 प्रतिशत हैं। सबसे ज्यादा ये दिल्ली में हैं – 7०.8 प्रतिशत जबकि सबसे कम 6०.1 प्रतिशत बिहार में हैं। देश में न सिर्फ कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है, बूजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। सन् 2०23 में 60 बरस से ऊपर वालों की आबादी 9.7 प्रतिशत हो गई है। ऐसी आबादी केरल में सर्वाधिक, 15.1 प्रतिशत है। जहां कामकरने वालों की संख्या का बढ़ना देश के लिए शुभ लक्षण है वहीं वृद्धों की संख्या के बढ़ने का अर्थ देश के नीति निर्माताओं के दायित्व में वृद्धि है।

इनमें से अधिकांश जानकारीयां यह बताती हैं कि बावजूद सारी अन्य बातों के देश एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है उसके बढ़ने की गति हमारी अपेक्षाओं से कम हो, यह निश्चित है कि वह बढ़ रहा है। हम यही कामना कर सकते हैं कि आगे बढ़ने की यह गति और अधिक तेज हो और हमारी सरकारें इस मानव संसाधन का अधिक सार्थक उपयोग करे और इस आबादी को बेहतर ज़िंदगी देने के अपने प्रयासों को और अधिक गति दे।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

राशिकल

सोमवार 15 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत् 2०82, मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 7:32 तक, व्यतिपात योग रात्रि 3:34 तक, तैत्तिल करण दिन 3:19 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-सिंह, गुरु-

मिथुन, शुक-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग योग सूर्योदय से प्रातः 7:32 तक है। आज मृत नवमी, नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवतीना श्राद्ध, व्यतिपात पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:47 तक, शुभ 9:14 से 1०:51 तक, चर 1:54 से 3:25 तक, लाभ-अमृत 3:25 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:3० से 9:०0 तक। सूर्योदय 6:1६, सूर्यास्त 6:28



महावीर सिंह

27 सितंबर 1925 को स्थापित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसके संबंध में सार्वजनिक रूप से बहुत सी सही, बहुत सी गलत और बहुत सी भ्रामक सामग्री, बातें उपलब्ध हैं। एक साधारण से उदाहरण के लिए इसकी शाखाओं और सदस्य संख्या को ही ले ले -- इसके 40 लाख से अधिक स्वयं सेवक बताए जाते हैं और 7० से 80 हजार के बीच शाखाएं बताई जाती हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्वयं सेवक (वॉलंटियर्स का) संगठन बताया जाता है किंतु यह भी कि इसके सदस्यों का शाखाओं की कोई अधिकृत, केंद्रीकृत सूचना कहीं मिलती नहीं है। गोपनीय रूप से होगी, सार्वजनिक तो नहीं है। यह भी अनुभव के आधार पर सही प्रतीत होता है कि बर केंद्र में या किसी प्रांत में भाषा सरकार होती है तो शाखाओं की व स्वयं सेवकों की संख्या बहुत बढ़ती है और फिर कम भी होती रहती है। इसका एक समझ में आने आला कारण तो यह प्रतीत होता है कि कई लोग शाखा इस लिए ज्वइन करते हैं कि उनके या उनके मिलने वालो के, सरकार से होने वाले काम कुछ आसानी से हो जाएं या छोटे स्तर पर कुछ लोग अपना राजनीतिक प्रभाव थोड़ा बढ़ा सकें। शाखाएं भी कई नामों वाली हैं जैसे प्रातः शाखाएं, सांयकालीन व मिलन शाखाएं, सप्ताह व महीने में एक बार एकत्र होकर चर्चा करने वाली शाखाएं आदि-आदि।

हर संगठन चाहे किसी कानून में पंजीकृत अथवा न हो किंतु उसकी कार्यविधि व संचालन की कोई न कोई नियमावली जरूर होती है किंतु की ऐसी नियमावली सार्वजनिक रूप से तो पढ़ने में भी काफी कमी आई है। इसका श्रेय बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षाओं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ी हुई जागरूकता और बेहतर जीवन स्थितियों को दिया जा सकता है। 1971 में देश में मृत्यु दर 1४.9 थी जो 2023 में घटकर ६.4 रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह इसी अवधि में 7.2 से घटकर ६.8 और शहरी क्षेत्रों में ६.० से 5.7 हुई है। अपने राजस्थान में वर्तमान मृत्यु दर 5.9 है। शहरों में यह 5.६ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6.० है। 2023 में सर्वाधिक मृत्यु दर ८.3 छत्तीसगढ में तो सबसे कम 4.० चंडीगढ में पाई गई है। और जब हम मृत्यु दर की बात कर रहे हैं तो शिशु मृत्यु दर की चर्चा भी कर लेनी चाहिए। असल में शिशु मृत्यु दर को स्थूल रूप से किसी देश या क्षेत्र विशेष का समग्र स्वास्थ्य परिचायक तथ्य माना जाता है। किसी खास इलाके में होने वाले एक हजार जन्मों में से एक वर्ष तक की आयु वाले कितने बच्चे काल कवलित हो जाते हैं उसी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह देखना बहुत आश्चरित्दायक है कि जहां 1971 में यह शिशु मृत्यु दर 129 थी वहीं 2023 में यह बहुत कम होकर मात्र 25 रह गई है। हालांकि यह संख्या भी अपेक्षणीय नहीं है, यह देखा जाना चाहिए कि हम कहां से कहां आ सके हैं। पिछले एक दशक में ही हमारी शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 25 हुई है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 28 और शहरी क्षेत्रों में 18 है। राजस्थान में यह शिशु मृत्यु दर टाामीण क्षेत्रों में 31, शहरी क्षेत्रों में 23 और समग्रतः 29 है। देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 37 छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है जबकि सबसे कम शिशु मृत्यु दर केवल 3 मणिपुर में है। शिशु मृत्यु दर की एक और गणना अंडर 5 मृत्यु दर के रूप में भी की जाती है। पिछले केवल एक बरस में यह अंडर 5 मृत्यु दर 3.० से घटकर 2.9 हो गई है। यहां यह बात खास तौर पर गौर तलब है कि इस उत्साह बढ़ाने वाली गिरावट के बावजूद यह एक त्रासद तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम हर चालीस में से एक शिशु अपनी उम्र का एक साल पूरा होने से पहले यह दुनिया छोड़ जाता है।

इस सर्वेक्षण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में ये हैं: सन् 2०23 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र प्रजनन दर 1.9 है। समग्र प्रजनन दर का आशय यह है कि कोई स्त्री अपनी प्रजनन क्षमता वाले वर्षों में औसतन कुल कितने बच्चों को जन्म देगी। दूसरी बड़ी बात यह कि देश में 14 बरस तक की आयु वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, और इसी के बरक्स यह तथ्य भी कि कामकाजी उम्र (15 से 59) वालों की संख्या बढ़ रही है। जहां तक कामकाजी उम्र वालों की संख्या बढ़ने की बात है, 1971-81 वाले दशक में यह 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 5६.3 प्रतिशत हुई थी। इसके बाद 1991 से 2023 के बीच यह बढ़कर 66.1 प्रतिशत हो गई है। शहरी क्षेत्रों में कामकाजी उम्र के लोग 68.8 प्रतिशत हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे थोड़े कम, 64.6 प्रतिशत हैं। सबसे ज्यादा ये दिल्ली में हैं – 7०.8 प्रतिशत जबकि सबसे कम 6०.1 प्रतिशत बिहार में हैं। देश में न सिर्फ कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है, बूजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। सन् 2०23 में 60 बरस से ऊपर वालों की आबादी 9.7 प्रतिशत हो गई है। ऐसी आबादी केरल में सर्वाधिक, 15.1 प्रतिशत है। जहां कामकरने वालों की संख्या का बढ़ना देश के लिए शुभ लक्षण है वहीं वृद्धों की संख्या के बढ़ने का अर्थ देश के नीति निर्माताओं के दायित्व में वृद्धि है।

इनमें से अधिकांश जानकारीयां यह बताती हैं कि बावजूद सारी अन्य बातों के देश एक बेहतर कल की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है उसके बढ़ने की गति हमारी अपेक्षाओं से कम हो, यह निश्चित है कि वह बढ़ रहा है। हम यही कामना कर सकते हैं कि आगे बढ़ने की यह गति और अधिक तेज हो और हमारी सरकारें इस मानव संसाधन का अधिक सार्थक उपयोग करे और इस आबादी को बेहतर ज़िंदगी देने के अपने प्रयासों को और अधिक गति दे।

—अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

कोटा, (निसं)। त्रौहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा गांपपुर सिटी, बयाना, इंदौराह, टुंडला, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पं.दीन दयाल उपाध्याय जं., भबुआ रोड, सासारा, डेहरी-आन-सोन, अनुग्रह नगर रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, गोमो, धनबाद, असनसोल, दुर्गापुर, बर्दमान एवं सियालदह स्टेशनों पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। कोच संरचना-इस विशेष ट्रेन में 5 शयनयन श्रेणी, 1० वातानुकूलित तृतीय श्रेणी एवं ०1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होंगे।

गंगापुर सिटी एवं 13.28 बजे बयाना स्टेशनों पर उठरते हुए शुक्रवार 16.15 बजे सियालदह पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या ०9438 सियालदह-गांधीधाम का संचालन दिनांक 2०, 27 सितम्बर एवं 4, 11 अक्टूबर 2025 को कुल 4 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन मार्ग में रविवार को 5.45 बजे बयाना, 7.4० बजे गंगापुर सिटी, 1०.25 बजे कोटा, 11.37 बजे रामगंजमंडी एवं 12.०7 बजे भवानीमंडी स्टेशनों पर उठरते हुए सोमवार तड़के 2.०० बजे गांधीधाम पहुंचेगी। यह गाड़ी रास्ते में दोनों दिशाओं में गांधीधाम,

समिति, सहकार भारती, हिंदू स्वयंसेवक संघ, लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच, क्रीड़ा भारती, विद्या भारती, विवेक नंद केंद्र, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, गौ रक्षक दल आदि-आदि कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी RSS का एक सहयोगी, अनुषांगिक संगठन ही है। है या नहीं यह निष्कर्ष, व भाजपा के बड़े नेताओं के विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर दिए जाने वाले बयानों से पाठक स्वयं निकाले।

विश्व हिंदू परिषद देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर हिंदुत्व विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है। 1९84 में स्थापित बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की युवा सखा है। गौ रक्षा दल, हिंदू वाहिनी के भी RSS से संबंध है।

RSS के अनुसार उसके अनुषांगिक संगठन समूज के वंचित समुदायों, कमजोर आर्थिक स्थिति वालों, कच्ची बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता संबंधित कार्य करते हैं। धार्मिक मुद्दों व हिंदुत्व के मुद्दों पर काम भी इन संगठनों के जरिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त RSS के लोग एक शब्द बहुदा काम लेते हैं वह है प्रकल्पा। इसके विभिन्न संगठन विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं और जन सहयोग से RSS के उद्देश्यों (हिंदुत्व) के अनुरूप परिणाम था बड़े पैमाने पर मुस्लिम जागत में अशांति। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में इस 192० से 193० की अवधि में कई हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। 1919 के जलियांवाला गोलिकांड के भयंकर नरसंहार के बाद, 192० से 193० का काल आजादी से पूर्व भारत के लिए एक झकझोरने वाला त्रासदियों का काल रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की राई चेतना, आजादी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गांधीजी के रूप में भारत में RSS हिंदू मुस्लिम एकता चाहती थी। गांधीजी के रूप में देश में नया नेतृत्व पनप रहा था जिसका मूलमंत्र था अंग्रेजी सरकार से अहिंसात्मक असहयोग तथा अन्यायपूर्ण आदेशों, हिंदेशी माल का बहिष्कार। कुछ अतिवादी तत्व गांधीजी के इन प्रयासों के विरुद्ध थे।

इसी काल में संघ के संस्थापक हेडगेवारजी के भी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू की किंतु शीघ्र ही उनका गांधीजी व कांग्रेस की नीतियों से मोहभंग हो गया। इसकी परिणति थी RSS का गठना। वैसे कांग्रेस ने तो 1९34 में अपने सदस्यों पर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के सदस्य होने पर रोक लगा दी थी। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि डाक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में इक्कठे होने वाले स्वयंसेवकों ने खुद को कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखा। हेडगेवारजी को विचारधारा हिन्दुओं को संगठित करके, हिंदुधर्म विरोधी ताकतों से हिंदुओं को अपनी रक्षा करने, अपनी संस्कृति और हिंदू मूल्यों(हिंदुत्व) की रक्षा व प्रसार करने के लिए प्रेरित करना था।इसकी परिणति हिंदू राष्ट्र के रूप में करने की थी। इसे हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा भी कह सकते हैं। सही, गलत या आंशिक सही, किंतु RSS की स्थापना के समय से ही इस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगात आया है जिसे RSS कभी नहीं मिटा पाया या राजनीतिक प्रभुत्व बनाई रखने के लिए, स्वयं इसे मिटाना चाहता नहीं।

स्थाना के समय से ही RSS पर आरोप लगा है कि आजादी के आंदोलन

करती ना।एए पर 3.4 बार सरकारी बैन भी लग गए तो भी कुछ नहीं हुआ अर्थात स्वेच्छिक स्वयं सेवी RSS की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की गतिविधियों को चलाने के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। इंकमटैक्स एक्ट की धारा 10(23c) के अनुसार लाभ नहीं कमाने वाले चैरिटेबल संगठनों पर इंकमटैक्स की भी देयता नहीं बनती।

RSS जानकारों का कहना है कि जो अनुषांगिक संगठन जनहित के कार्य करते हैं और किसी प्रकार की बाह्य आर्थिक सहायता लेते हैं वे सब आवश्यक कानूनों के अनुसार सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके ही कार्य करते हैं। प्राप्त सहायता का लेख, अंकेक्षण सब यथा विधि पूर्ण कराए जाते हैं।

कुछ ऐसे मुद्दे जो RSS का कभी पीछा नहीं छोड़ते :-- 1914 से 1919 तक चला प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हुआ। उसका परिणाम था तुर्क में नया शासन, खलीफा का महत्व समाप्त, मध्य एशिया के मुस्लिम क्षेत्रों का विजेताओं के अनुरूप विभाजन, नई सीमाएं। इसका परिणाम था बड़े पैमाने पर मुस्लिम जागत में अशांति। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में इस 192० से 193० की अवधि में कई हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। 1919 के जलियांवाला गोलिकांड के भयंकर नरसंहार के बाद, 192० से 193० का काल आजादी से पूर्व भारत के लिए एक झकझोरने वाला त्रासदियों का काल रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की राई चेतना, आजादी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गांधीजी के रूप में भारत में RSS हिंदू मुस्लिम एकता चाहती थी। गांधीजी के रूप में देश में नया नेतृत्व पनप रहा था जिसका मूलमंत्र था अंग्रेजी सरकार से अहिंसात्मक असहयोग तथा अन्यायपूर्ण आदेशों, हिंदेशी माल का बहिष्कार। कुछ अतिवादी तत्व गांधीजी के इन प्रयासों के विरुद्ध थे।

इसी काल में संघ के संस्थापक हेडगेवारजी के भी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू की किंतु शीघ्र ही उनका गांधीजी व कांग्रेस की नीतियों से मोहभंग हो गया। इसकी परिणति थी RSS का गठना। वैसे कांग्रेस ने तो 1९34 में अपने सदस्यों पर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के सदस्य होने पर रोक लगा दी थी। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि डाक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में इक्कठे होने वाले स्वयंसेवकों ने खुद को कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखा। हेडगेवारजी को विचारधारा हिन्दुओं को संगठित करके, हिंदुधर्म विरोधी ताकतों से हिंदुओं को अपनी रक्षा करने, अपनी संस्कृति और हिंदू मूल्यों(हिंदुत्व) की रक्षा व प्रसार करने के लिए प्रेरित करना था।इसकी परिणति हिंदू राष्ट्र के रूप में करने की थी। इसे हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा भी कह सकते हैं। सही, गलत या आंशिक सही, किंतु RSS की स्थापना के समय से ही इस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगात आया है जिसे RSS कभी नहीं मिटा पाया या राजनीतिक प्रभुत्व बनाई रखने के लिए, स्वयं इसे मिटाना चाहता नहीं।

स्थाना के समय से ही RSS पर आरोप लगा है कि आजादी के आंदोलन

से संगठन ने दूरी बनाके रखी, सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और हमेशा उपनिवेशी ताकत के साथ सहयोगात्मक रख अपनाया। यद्यपि अप्रैल 193० के नमक सत्याग्रह में डाक्टर हेडगेवार में भाग लिया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निर्णय अनुसार 36 जनवरी 193० को स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसमें RSS ने भाग लिया किंतु वह अंतिम बार था। शायद RSS का मानना था कि वह जिस राष्ट्र, चरित्र निर्माण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति में लगा है उसके लिए जरूरी था कि उसका कोई काम ब्रिटिश विरोधी न लगे और सरकार उसके काम में अवरोध उत्पन्न करे।

RSS से जुड़ी कुछ अन्य धारणाएं हैं कि इस संगठन में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्र ध्वज तिरंगे ध्वज को कभी में से स्वीकार नहीं किया। इसे अशुभ माना गया। यह संगठन इसके स्थान पर केसरिया ध्वज को सामान्यत किसी मंदिर, धार्मिक स्थान पर देखने को मिलता है, उसे राष्ट्र ध्वज चाहते थे।इस संगठन ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय पर वर्ष 20०० से पहले तिरंगा फहराया भी नहीं,यह आरोप भी लगाता है।एए के शीर्ष नेताओं में भारत के संविधान के लिए भी सार्वजनिक रूप से कहा कि इसमें भारतीय शास्त्रीय व सांस्कृतिक मूल्यों का कोई समावेश नहीं। यह पश्चिमी देशों के संविधानों की नकल है। यह सब बातें उस समय के एए के मुखपत्र ऑर्गनाइजर आदि में छपे लेखों के आधार पर कही जाती हैं।

आपने शायद यह कई बार सुना होगा कि भाजपा, RSS का ध्येय, सपना अखंड भारत स्थापित करने का है। यह कहा कि राष्ट्र नहीं किया जाता कि कौन सा अखंड भारत --चन्द्रगुप्त मौर्य या महान सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त या चन्द्रगुप्त क्रिमाहत्याय का कालिक या हर्ष या हम्पी का विजयनगर साम्राज्य या चोल राजाओं का साम्राज्य या किसी अन्य राजा के समय जो सीमाएं थी उन्हें अखंड भारत की सीमाएं मानकर प्रयास कर रहे हैं?? और एक वाक्य बोलने के अतिरिक्त क्या प्रयास किया?इसे कभी स्पष्ट नहीं किया जाता। हमेशा भ्रम बनाए रखा जाता है।

RSS शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस,ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को, हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव मनाती है,क्या इसमें अखंड भारत की झलक मिलती है? विस्तार की दृष्टि से तो शिवाजी महाराज के राज्य की सीमाएं, ऊपर उल्लेखित किसी भी साम्राज्य की तुलना में, बहुत सीमित थी। एए के अनुसार वह साम्राज्य सुशासन का प्रतीक था जिसमें निर्णय असात्यों के साथ चर्चा कर रहमती से किए जाते थे। यदि मुगलों से सामना करने की बात के आधार पर कोई उत्सव मनाया जाए तो फिर महाराणा प्रताप और महाराजा सुरजमल ने भी डटकर मुगलों का सामना किया था।

RSS से या किसी से भी, एक प्रश्न है कि क्या आज के संवैधानिक भारत की तुलना में इन में से कोई भी राज्य श्रेष्ठ था और कैसे? आज आदमी को जो संवैधानिक अधिकार आज हैं वैसे किसी और काल खंड में थे?? एक अन्य मुद्दा जो कई बार जन चर्चा में उछला जाता है, वह है कि उस समय के आजादी के सेना नायकों ने राज्य की लालसा की जल्दबाजी में भारत

का विभाजन स्वीकार किया।और क्या विकल्प हो सकता था, इसको हमेशा अस्मष्ट रखा जाता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हैसियत एक आर्थिक, सामरिक महाशक्ति वाली नहीं रही। उसको हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही था। अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर दिया था। उन्होंने देशी रियासतों को एक विकल्प यह भी दे दिया कि वे स्वतंत्र रह सकते थे।

56० से ऊपर देशी राज्यों के लिए एए के पास क्या विकल्प था? क्या उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाता?? क्या गांव, देहात, कच्ची बस्तियां गरीब,मजदूर किसानों को निरंकुश रजवाड़ों की दया पर ही छोड़ दिया जाता? क्या इन रजवाड़ों को विभाजन स्वीकार करने वाले नेताओं ने ही भारत संघ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया? देशी रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों को संविधान निर्मात्री सभी में शामिल कर के देशी रजवाड़ों को साफ संदेश दे दिया था कि वे, उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि आजादी के जंग से जुड़ी जनता के आक्रोश को वे सहन नहीं कर पायेंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि देशी रियासतों की राज्यव्यवस्था उस समय के अभिजात वर्ग की अत्यंत अनुकूल थी और गरीब जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे या नुमाइशी तौर पर नाम मात्र थे। हिंदू महासभा में इसी अभिजात वर्ग के लोग जो थे।

वैसे कुछ निम्नक्ष इतिहासकारों का मानना है कि भारत विभाजन के लिए ब्रिटेन, हिंदू महा सभा के अग्रणी नेता, जिजा और मुस्लिम लीग वो दामोदर सागरकर के द्वि राष्ट्र के विचार या हिंदू-मुस्लिन दो राष्ट्र के विचार लेते थे?

कुछ लोग प्रश्न पूछ लेते हैं,RSS में महिलाओं का क्या स्थान है? RSS के जानकार केवल यह कहते हैं कि महिलाओं के लिए महिला राष्ट्र सेविका समिति अनुषांगिक संगठन है। किंतु यह इसका उतर नहीं हो सकता कि क्या कभी कोई महिलाएं एए की सरसंच चालक या सहकार्यवाह बन सकती हैं क्या??

इसी प्रकार पूछने वाले तो पूछते ही रहते हैं कि सरसंच चालक का चयन कैसे होता है? आज से करीब 6,7 साल पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में RSS के बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम था। उसमें यही प्रश्न श्री मोहन भागवत जी से पूछा गया था। उनका उतर था....।किसी में मेरा चयन किया, किसी को मैं चुन लूंगा....।छेर यह रहस्य और आंतरिक मामला है और स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सरसंचचालक का चुनाव वर्तमान सरसंच चालक के मनोनयन को प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन (जो मात्र औपचारिकता होती है) से होता है। पद की कोई समयावधि नहीं होती। जब सरसंच चाहेगा तब वे स्वयं पद छोड़ देते हैं। इसी प्रकार समय समय पर कुछ और भी विचार उछाले जाते हैं जैसे हिंदुओं, मुसलमानों का DNA एक ही है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, हिंदुओं की वजह से ही भारत धर्म निरपेक्ष है वगैर। लगातार अस्मष्ट, भ्रामक बयान देने रहना RSS की सोची-समझी रणनीति होती है ताकि राजव्यवस्था में हिंदुओं और मुख्यत पूर्व वाले अभिजात वर्ग का प्रभुत्व बना रहे।

—महावीर सिंह, पूर्व आई ए एस

तयौहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिये विशेष ट्रेनों का संचालन

कोटा, (निसं)। त्रौहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा गांपपुर सिटी, बयाना, इंदौराह, टुंडला, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पं.दीन दयाल उपाध्याय जं., भबुआ रोड, सासारा, डेहरी-आन-सोन, अनुग्रह नगर रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, गोमो, धनबाद, असनसोल, दुर्गापुर, बर्दमान एवं सियालदह स्टेशनों पर ठहराव लेकर गंतव्य को जाएगी। कोच संरचना-इस विशेष ट्रेन में 5 शयनयन श्रेणी, 1० वातानुकूलित तृतीय श्रेणी एवं ०1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 18 डिब्बे होंगे।

गंगापुर सिटी एवं 13.28 बजे बयाना स्टेशनों पर उठरते हुए शुक्रवार 16.15 बजे सियालदह पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या ०9438 सियालदह-गांधीधाम का संचालन दिनांक 2०, 27 सितम्बर एवं 4, 11 अक्टूबर 2025 को कुल 4 फेरों के लिए किया जाएगा। यह ट्रेन मार्ग में रविवार को 5.45 बजे बयाना, 7.4० बजे गंगापुर सिटी, 1०.25 बजे कोटा, 11.37 बजे